VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2213)

Name of Candidate	VIKAS GUPTA		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	137029
Center	online	Date	21/08/2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. An effective approach to green budgeting is underpinned by strong strategic framework, tools for evidence generation and an enabling budgetary governance framework. Discuss. **(150 words) 10**

हरित बजट के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण को सुदृढ़ रणनीतिक ढांचे, साक्ष्य निर्माण हेतु उपकरण और एक सक्षम बजटीय शासन ढांचे द्वारा सुदृढ़ता प्रदान की जाती है। विवेचना कीजिए।

हरित बजट से तात्पर्य सरकार द्वारा बजट निर्माण प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिक तंत्र को उचित महत्व देने से है।

आवश्यकता

- बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। (विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 14 भारत से)
- जलवायु परिवर्तन को न्यूनतम करने के लिए।
- जैव विविधता व देशज समुदाय की आजीविका संरक्षण हेतु।

हरित बजट के आवश्यक कारक

1. **सुदृढ़ रणनीतिक ढांचा** — इसके अंतर्गत बजट में पर्यावरण संबंधी विशिष्ट उपायों को ~~उपाया~~ अपनाया जाता है जैसे हालिया बजट में थर्मल पावर प्लांट में बायोमास को-फायरिंग का प्रावधान।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

साथ ही इसके अंतर्गत बजट के माध्यम से दीर्घकालिक व अल्पकालिक उपायों को एकीकृत किया जाता है।

2. साक्ष्य निर्माण हेतु उपकरण - इसके अंतर्गत बजट में किये गये प्रयासों के प्रभाव की निगरानी हेतु व्यवस्था की जाती है।
इससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है एवं योजना की प्रभाविता सुनिश्चित होती है।

3. सक्षम बजटीय शासन ढाँचा -
इसमें बजट की अन्य योजनाओं को पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। साथ ही वित्त की उचित व्यवस्था होती है।

इस प्रकार हरित बजटिंग को संधारणीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है।

2. State the need for circular economy in India and the challenges associated with it. Also, discuss the measures that are required to build a circular economy in India. **(150 words) 10**

भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता और इससे जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, भारत में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।

चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं के पुनः उपयोग को बढ़ावा देकर संधारणीय विकास का प्रयत्न किया जाता है। इसे 3R अर्थव्यवस्था या रिड्यूस (कम उपयोग), रियूज (पुनः उपयोग), रिसाइकिल भी कहा जाता है।

भारत के लिए आवश्यकता

→ आयात पर निर्भरता कम करने के लिए। जैसे सोलर पैनल की रिसाइकलिंग करना जिसका 80% भाग वर्तमान में चीन से आयातित।

→ ~~आप~~ अपशिष्ट का संधारणीय निस्तारण करने के लिए क्योंकि वर्तमान में भारत में अपशिष्ट की ~~मा~~ मात्रा बढ़ रही है।

→ पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायक जैसे काँच की बोतलों का पुनः उपयोग करना अन्यथा वे मृदा प्रदूषण का कारण।

→ देश की बहुमूल्य आर्थिक संपदा की रक्षा करने के लिए।

चुनौतियाँ

- रिसाइकलिंग से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी व शोध की कमी।
- जनता द्वारा घरों में अपशिष्ट का पृथक्करण न किया जाना।
- ज्यादातर अपशिष्ट का प्रबंधन असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जिनके पास रिसाइकलिंग संबंधी तकनीक की कमी।

उपाय → विकसित राष्ट्रों से सहयोग जैसे वर्तमान में यूरोपियन 90% मेटल का पुनः प्रयोग करता है।

→ लोगों को घरों पर अपशिष्ट पृथक्करण के संबंध में जागरूक करना।

→ ~~लोगों~~ कंपनियों को चक्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए प्रोत्साहन।

इस प्रकार ~~वास्तव में~~ चक्रीय अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को संधारणीय बना सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. The Major Port Authorities Act, 2021, seeks to grant greater autonomy and flexibility to the major ports and professionalise their governance. Discuss. (150 words) 10

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021, प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने तथा उनके शासन को पेशेवर बनाने का प्रयास करता है। विवेचना कीजिए।

प्रमुख बंदरगाह भारत में ऐसे बड़े बंदरगाह हैं जिनका विनियमन सामान्यतः केंद्र/संघ सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह आदि।

इसी संदर्भ में प्रमुख बंदरगाहों के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 पारित किया गया। यह निम्न प्रकार से बंदरगाहों की स्वायत्ता, लचीलेपन व पेशेवर में सुधार करेगा :-

→ हर बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण का गठन किया जायेगा

→ बंदरगाह प्राधिकरण ~~का~~ अपने बंदरगाहों के निर्धारित कार्यों को निजी क्षेत्र को

सौंपने में सक्षम होगा।

→ सरकार द्वारा प्राधिकरण के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

→ प्राधिकरण बंदरगाह में विभिन्न शुल्कों के प्रबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

वर्तमान में भारत में विभिन्न बंदरगाहों की दक्षता व क्षमता विकसित देशों के बंदरगाहों की तुलना में 40% से 50% है। इस अधिनियम के माध्यम से इस दक्षता में सुधार कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व भारतीय अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन पहुँचने में मदद मिलेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Analyse the need for shifting from presumptive land titling to conclusive land titling system in India. Also, highlight the hurdles in its implementation. **(150 words) 10**

भारत में अनुमानित भूमि स्वामित्व से निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली में स्थानांतरण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इसके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को रेखांकित कीजिए।

भारत में आजादी के बाद से भू-स्वामित्व की अनुमानित स्वामित्व की अवधारणा को अपनाया गया। इसके अंतर्गत जमीन पर उस व्यक्ति का अधिकार मान लिया जाता है जो एक निश्चित समय से वहाँ रह रहा हो।

तथापि इस स्वामित्व को निर्णायक नहीं माना जाता तथा कोई व्यक्ति इसे चुनौती दे सकता है।

निर्णायक भूमि स्वामित्व की आवश्यकता

→ भू-विवादों के खत्म होने से भूमि-अधिग्रहण व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी।

→ निर्णायक भू-स्वामित्व से व्यक्ति को जमीन गिरवी रख ऋण प्राप्त करने में आसानी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जिससे उद्यमशीलता व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि।

→ कृषि में निवेश में वृद्धि की संभावना।

→ न्यायपालिका पर बोझ में कमी क्योंकि निचली अदालतों में भूमि विवाद ही लंबित वादों का बड़ा हिस्सा।

क्रियान्वयन में बाधाएँ

- → अंग्रेजी शासनकाल में जमींदारी व्यवस्था के कारण वास्तविक मालिक की पहचान कठिन।
- → लोगों के पास पुराने दस्तावेजों का अभाव।
- → राज्य सरकारों द्वारा नियमित रूप से भू-स्वामित्व डेटा का अद्यतन नहीं

सरकारी प्रयास → (1) स्वामित्व योजना।
(2) राष्ट्रीय भू रिकॉर्ड डिजीटलीकरण योजना।

इन प्रयासों से भू-स्वामित्व की निर्णायक प्रणाली को अपनाकर कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का उद्धार किया जा सकेगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. What do you understand by methanol economy? Critically discuss its role in achieving India's energy security and economic prosperity. **(150 words) 10**

मेथनॉल अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में इसकी भूमिका की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

मेथेनॉल अर्थव्यवस्था से तात्पर्य मेथेनॉल ईंधन पर आधारित अर्थव्यवस्था से है। मेथेनॉल एक कम कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन ईंधन है।

इसे एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग शून्य SO_2, शून्य N_2O का उत्सर्जन होता है, साथ ही वसकी ऑक्टेन संख्या उच्च है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा व आर्थिक समृद्धि में भूमिका

→ डीजल व पेट्रोल में मेथेनॉल मिश्रण के माध्यम से आयात पर निर्भरता कम कर चालू खाता घाटा में कमी।

→ विदेशी ईंधन पर निर्भरता में कमी से ईंधन संबंधी मूल्य अस्थिरता से महंगे

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

का बचाव जैसे हाल ही में यूक्रेन संकट के कारण पेट्रोल, डीजल के दामों में वृद्धि।

→ सतत ऊर्जा/ईंधन के रूप में भारत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति में सहायक।

→ मेथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन होने के कारण प्रदूषण कम करने व भारत की पेरिस लक्ष्यों या NDC की प्राप्ति में मददगार।

बाधाएं

→ वर्तमान में मेथेनॉल का निर्माण मुख्यतः कोयले से जिससे वायु प्रदूषण।

→ मेथेनॉल मिश्रित ईंधन की दक्षता शुद्ध पेट्रोल/डीजल ईंधन से कम।

→ मेथेनॉल निर्माण हेतु नवीन प्रौद्योगिकी का अभाव।

इस संबंध में सरकार को निजी क्षेत्र द्वारा शोध बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए जिससे हरित तकनीक से मेथेनॉल का निर्माण व मेथेनॉल अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Discuss the role of geospatial technologies in developing effective approaches for disaster risk reduction and disaster management.

(150 words) 10

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी दृष्टिकोण विकसित करने में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

भारत को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुभेद्य माना जाता है। जैसे देश का 68% कृषि भूमि सूखे, 12% भाग बाढ़, 75% तटरेखा चक्रवात के प्रति सुभेद्य है।

इस संदर्भ में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तकनीक में उपग्रहों के माध्यम से सुभेद्य क्षेत्र के पूरे भौगोलिक आयाम को ध्यान में रखकर आपदा प्रबंधन का प्रयास किया जाता है। इसमें GIS, GPS, नाविक जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन में भूमिका :-

→ विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन से एकीकृत योजना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्माण में सहायता जैसे बाढ़ प्रबंधन हेतु वाटरशेड मैनेजमेंट।

→ क्षेत्र के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लिए संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने में।

→ क्षेत्र में स्थित विभिन्न गाँवों व शहरों के प्रशासन को उचित रूप से नीति निर्मित करने व योजना निर्माण में मदद।

इस संदर्भ में इसरो का भुवन प्लेटफॉर्म व नाविक प्रणाली सहायक हो सकती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The focus of Environmental Impact Assessment (EIA) needs to shift from utilization and exploitation of natural resources to conservation of natural resources. Discuss. **(150 words) 10**

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का मुख्य ध्यान प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और दोहन से हटाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित होना चाहिए। विवेचना कीजिए।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से तात्पर्य किसी परियोजना के पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का आकलन करना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत EIA का प्रावधान का किया गया है।

वर्तमान में EIA का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर केंद्रित है। जिस कारण पर्यावरण को अत्यधिक क्षति न पहुँचने पर सामान्यतः प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी जाती है।

दुष्प्रभाव

→ निर्वनीकरण व जैव विविधता की हानि।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के साधनों की कमी।

→ भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं की संभावना में वृद्धि जैसे हाल ही में मेघालय में भूस्खलन के कारण यहाँ रेल्वे लाइन निर्माण कार्य को माना गया।

वास्तव में EIA का ध्यान a पर्यावरण के संरक्षण की ओर होना चाहिए।

सकारात्मक प्रभाव

→ भारत के पेरिस समझौते के क्रियान्वयन में सहायता।

→ पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. What do you understand by hybrid warfare? Discuss India's preparedness in this context. (150 words) 10

हाइब्रिड वारफेयर से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में, भारत की तैयारियों की विवेचना कीजिए।

हाइब्रिड वारफेयर, आधुनिक युद्ध का प्रकार है जिसमें देश अन्य देश से परंपरागत युद्ध न करके साइबर हमलों, सिविल सोसायटी की मदद से आंतरिक सुरक्षा में परेशानी के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है।

भारत द्वारा हाइब्रिड वारफेयर संबंधी तैयारियाँ

→ साइबर स्पेस सुरक्षित रखने 2020 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का निर्माण

→ साइबर अपराधों से बचाव CERT-IN का निर्माण।

→ रक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा प्रयास।

→ क्रिटिकल अवसंरचनाओं की रक्षा हेतु NCIIPC का निर्माण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ NGOs के कार्यों में पारदर्शिता लाने FCRA, 2010 में संशोधन।

→ अंतरिक्ष में भारत की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ~~AST~~ ASAT मिशन।

कमियां

→ साइबर स्पेस में भारत के प्रयास केवल रक्षात्मक प्रयासों तक सीमित। जबकि चीन जैसे राष्ट्र आक्रामक उपाय अपना रहे हैं।

→ भारत की संचार उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भरता।

→ सरकार व सिविल सोसायटी के मध्य बढ़ता अलगाव।

इस संबंध में भारत को साइबर स्पेस सुरक्षित रखने निजी क्षेत्र से सहयोग करना चाहिए व सिविल सोसायटी से संपर्क मजबूत करने चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Discuss the challenges associated with inclusion of women in armed forces, particularly in combat roles in India. How can these challenges be addressed? **(150 words) 10**

सशस्त्र बलों, विशेष रूप से भारत में युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने का विचार आजादी के बाद से ही विवाद का विषय रहा है। वर्तमान में भी सेना में महिलाओं की भूमिका मुख्यत: पुरुष सैनिकों के सहायक तक सीमित है।

युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने संबंधी चुनौतियाँ —

→ पितृसत्तावादी भावना - सामान्यत: पुरुष सैनिकों में पितृसत्तावादी भावना के कारण महिलाओं की भर्ती का विरोध किया जाता है। इस कारण जबरन भर्ती से सैनिकों के मध्य टकराव की संभावना।

→ महिलाओं को युद्धक भूमिका में शामिल करने से संबंधी कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भी हैं जैसे मासिक धर्म संबंधी समस्या।

→ कई विश्लेषकों के अनुसार महिलाएँ स्वभावतः प्रेम व दया दृष्टिकोण से युक्त होती हैं। ऐसे में महिलाओं को युद्धक भूमिका में शामिल करने से भारत की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

समाधान

→ पुरुष सैनिकों की मानसिकता में परिवर्तन करने हेतु प्रयास करना।

→ महिलाओं को उनकी व्यवहारिक समस्याओं को युद्धक भूमिका में बाधा न बनने देने हेतु ट्रेनिंग देना।

~~वास्त~~ युद्धक भूमिका में महिलाओं को शामिल करने को केवल लैंगिक समानता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। एवं समाधानों के माध्यम से उनकी भूमिका पर विचार करना चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. S. Chandrasekhar was one of the greatest scientists of the 20th century whose prolific contributions spanned across astrophysics, space and mathematics. Elaborate. **(150 words) 10**

एस. चंद्रशेखर 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनका खगोल भौतिकी (एस्ट्रोफिजिक्स), अंतरिक्ष और गणित के क्षेत्र में विपुल योगदान था। सविस्तार वर्णन कीजिए।

एस. चंद्रशेखर महान भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्हें ~~भौत~~ भौतिकी के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

योगदान

→ एस. चंद्रशेखर ने ~~पहले~~ ब्लैकहोल के संबंध में चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत दिया। यदि किसी तारे का द्रव्यमान इस सीमा से अधिक होता है तो उस तारे का ब्लैकहोल / न्यूट्रान तारा बनने की संभावना होती है।

वहीं यदि वह तारा इस सीमा से कम द्रव्यमान का होता है, तो वह ड्वार्फ तारे के रूप में समाप्त होता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. State finances in India present a worrying picture, with debt sustainability being a major concern. Discuss in context of the recent RBI report on state finances. **(250 words) 15**

भारत में राज्य वित्त एक चिंताजनक स्थिति प्रस्तुत करता है, जिसमें ऋण संधारणीयता एक प्रमुख चिंता का विषय है। राज्य वित्त पर आर. बी. आई. की हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

भारत की संघीय राजपद्धति में राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में स्वायत्त राजकोषीय नीति के माध्यम से शासन संचालन का कार्य करते है।

हालांकि हाल ही में RBI की रिपोर्ट ने राज्यों द्वारा अपनी नीतियों में राजकोषीय अनुशासन का पालन न करने के संबंध में चेतावनी दी है। इसके अनुसार राज्यों का सकल ऋण ~~सकल राज्य~~ GDP का 31% पहुँच गया है। जबकि N.K. सिंह समिति ने इसे G.D.P के 20% तक रखने की सिफारिश की थी।

कारण

→ राज्यों द्वारा लोकलुभावन घोषणाएं जैसे ऋणमाफी, मुफ्त बिजली प्रदान करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ राज्यों द्वारा बजट निर्माण में वास्तविक आय पर ध्यान न दिया जाना व ऋण के माध्यम से योजनाओं के वित्तपोषण पर निर्भरता।

→ GST के लागू होने के बाद से राज्यों के राजस्व में कमी। (2019-20 तक 17 राज्यों में राजस्व वृद्धि दर 10% से कम रही।)

→ कोविड-19 के कारण राज्यों के राजस्व में कमी। साथ ही नागरिकों की सहायता हेतु राज्यों द्वारा व्यय में वृद्धि।

निहितार्थ - ऋण संधारणीय न होने के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं-

→ राज्यों द्वारा बाजार से ऋण लेने पर निजी क्षेत्र के लिए ऋण में कमी (क्राउडिंग आउट इफेक्ट)

→ व्यय के अनुरूप आय न होने पर राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय में कमी की जा सकती

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

है, जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है।

→ लोकलुभावन योजनाओं पर अधिक व्यय होने पर नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यय कम होने की संभावना।

→ अत्यधिक ऋण होने पर श्रीलंका की तरह डिफाल्ट की संभावना।

उपाय

- राज्यों द्वारा राजकोषीय अनुशासन को अपनाना।
- राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज संस्कृति को बढ़ावा न देना।
- वित्त आयोग द्वारा राज्यों की ऋण संधारणीयता में मदद करना।
- राजकोषीय परिषद का गठन करना।

राज्यों की ऋण संधारणीयता अंततः पूरे भारत की आर्थिक व राजनीतिक स्थिरता हेतु अपरिहार्य है। इस संबंध में केंद्र को राज्यों की मदद की जानी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. The Indian experience provides several lessons of an inclusive digital economy model that enables formal digital governance structure at a low cost and with easier access. Discuss. **(250 words) 15**

भारतीय अनुभव एक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था मॉडल के कई सबक प्रदान करता है जो कम लागत पर और आसान पहुंच के साथ औपचारिक डिजिटल शासन संरचना को सक्षम बनाता है। विवेचना कीजिए।

भारत में ~~डिजिटल~~ 2016 की नोटबंदी व हाल ही में आई कोविड-19 आपदा के बाद से डिजिटल ~~अ~~अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वृद्धि हुई है। डिजिटल ट्रांजेक्शन 2014 में 2.2 प्रतिव्यक्ति से बढ़कर 2020 में 22 प्रतिव्यक्ति हो गये हैं। साथ ही 2025 तक भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के $1 ट्रिलियन (वर्तमान $200 बिलियन) पहुंचने की संभावना है।

भारत में ~~डिजिटल~~ समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के सबक :-

1. कम लागत पर डिजिटल शासन व्यवस्था :-
   - → विभिन्न ऐप्स के माध्यम से मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा जैसे पेटीएम, फोन-पे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ सरकार द्वारा पीओएस मशीनों की खरीद पर सब्सिडी।

→ RBI द्वारा MDR शुल्क का युक्तिकरण।

→ रुपे कार्ड के माध्यम से व जीरो-बैंक अकाउंट के माध्यम से छोटे आय वर्ग के लिए खाते का संचालन आसान हुआ।

2. आसान पहुँच युक्त डिजिटल शासन संरचना

→ UPI, भीम ऐप के माध्यम से लेनदेन में आसानी।

→ QR कोड की मदद से अलग-अलग बैंकों के माध्यम से सीमलेस कनेक्शन

→ RBI द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रभावी विनियमन।

→ प्रधानमंत्री जन-धन योजना, पेमेंट्स बैंक

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों व पिछड़े वर्गों का वित्तीय समावेशन।

सकारात्मक प्रभाव

→ औपचारिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता।

→ लोगों द्वारा बचत में वृद्धि से निवेश में वृद्धि।

→ औपचारिक अर्थव्यवस्था का बढ़ावा मिलने से कर वंचन की संभावना में कमी।

→ नीति निर्माण में आसानी।

चुनौतियाँ → ग्रामीण क्षेत्रों में धीमा इंटरनेट व डिजिटल अवसंरचना की कमी।

→ लोगों में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं में वृद्धि।

नीति आयोग के अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु नागरिकों नागरिकों में 100% डिजिटल साक्षरता का प्रयास करना चाहिए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Dairying is a viable livelihood option for a large section of the population. In this context, discuss the significance, challenges faced and associated government initiatives for the dairy sector in India. **(250 words) 15**

डेयरी व्यवसाय, आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का एक व्यवहार्य विकल्प है। इस संदर्भ में, इसके महत्व, विद्यमान चुनौतियों और भारत में डेयरी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा की गयी पहलों की विवेचना कीजिए।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राष्ट्र है। डेयरी व्यवसाय वर्तमान में भारतीय कार्यबल के लगभग 10% भाग को आजीविका उपलब्ध कराता है।

महत्व

→ जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादन में अस्थिरता के समय कृषकों की आय स्थिरता सुनिश्चित करने में।

→ डेयरी क्षेत्र में कृषकों को ग्राहक द्वारा देय मूल्य का 70% तक प्राप्त होता है जबकि सामान्य फसलों के विक्रय में कृषकों को मात्र 30% हिस्सा ही प्राप्त होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ डेयरी क्षेत्र महिलाओं के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत देता है। एक अनुमान के अनुसार 70% महिला कृषि कार्यबल डेयरी से जुड़ी है।

→ डेयरी क्षेत्र कुपोषण की समस्या खत्म करने के लिए भी महत्वपूर्ण।

→ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखे की स्थिति में फसल नष्ट होने पर आय का स्थिर स्रोत।

विद्यमान चुनौतियाँ

→ भारतीय डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता विकसित देशों की तुलना में कम (जैसे न्यूजीलैंड की तुलना में लगभग आधी।

→ डेयरी क्षेत्र में पशुओं से संबंधित रोग चिकित्सकों व अस्पतालों की कमी।

→ उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रजातियों की कमी।

→ पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे की कमी।

सरकार द्वारा की गई पहलें

→ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
→ राष्ट्रीय डेयरी मिशन।
→ राष्ट्रीय गोकुल कार्यक्रम।
→ प्रधानमंत्री संपदा योजना।
→ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण।

सुझाव

→ वन विभाग व ग्रामीणों के मध्य सहयोग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराना।
→ पशुओं की संकर नस्लों को बढ़ावा देने के लिए शोध को प्रोत्साहन।

डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर कृषि क्षेत्र के विकास के साथ कृषक आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. The imperative to increase farmers' income must shift to creating value chains and must not be reliant on the MSP regime and subsidy bias prevalent in the current Indian agricultural system. Examine.

(250 words) 15

किसानों की आय बढ़ाने की अनिवार्यता को मूल्य श्रृंखलाओं के सृजन से जोड़ा जाना चाहिए और इसे वर्तमान भारतीय कृषि प्रणाली में प्रचलित एम. एस. पी. व्यवस्था एवं पूर्वाग्रहयुक्त सब्सिडी पर कतई निर्भर नहीं होना चाहिए। परीक्षण कीजिए।

भारत में आजादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की संकल्पना को साकार करने MSP व्यवस्था एवं सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहन की प्रणाली अपनाई गई।

तथापि वर्तमान में MSP एवं सब्सिडी व्यवस्था के कई दुष्परिणाम सामने आए हैं जैसे :- [MSP के दुष्परिणाम]

→ फसल पैटर्न में परिवर्तन जैसे पंजाब जिसे सरसों व मक्के की खेती की पहचान थी वहाँ चावल एवं गेहूँ का उत्पादन।

→ जल गहन फसलों को बढ़ावा जैसे चावल व गन्ना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ मोनोकल्चर को बढ़ावा मिलने से फसल विविधीकरण पर विपरीत प्रभाव।

→ मोटा अनाज का उत्पादन कम होने से कुपोषण की स्थिति। (ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर)

सब्सिडी अवस्था के दुष्परिणाम

→ अत्यधिक जल दोहन के कारण जल तनाव की स्थिति।

→ उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल प्रदूषण एवं भूमि के बंजर होने की स्थिति।

→ असंतुलित उर्वरक प्रयोग से फसल उत्पादकता में कमी।

इस संदर्भ में भारतीय कृषि में मूल्य श्रृंखलाओं के सृजन को बढ़ावा देने को अपरिहार्य माना जा रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मूल्य श्रृंखला सृजन

→ बाजार की मांग के आधार पर उत्पादन को प्रोत्साहन।

→ कृषि में निवेश बढ़ाकर मशीनीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि।

→ भारतीय कृषि को विदेशी मार्केट से जोड़ना

→ शीत भंडारण श्रृंखला के माध्यम से फसल कटाई पश्चात हानि कम करना।

→ खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर उत्पाद के मूल्य में वृद्धि द्वारा कृषि को लाभकारी बनाना।

→ कृषि में सुचारु बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज

सरकारी प्रयास
- प्रधानमंत्री संपदा योजना।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना।
- ई-नाम।

इस प्रकार मूल्य श्रृंखला सृजन संधारणीय कृषि व सतत कृषक आय में सहायक होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. What are the challenges in ensuring sustainable river management in urban areas? Highlight the remedial measures that can be taken for river management with a special focus on the recently launched River Cities Alliance.
(250 words) 15

शहरी क्षेत्रों में संधारणीय नदी प्रबंधन को सुनिश्चित करने में कौन-सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं? हाल ही में प्रारंभ रिवर सिटीज एलायंस पर विशेष ध्यान देते हुए नदी प्रबंधन के लिए किए जा सकने वाले उपचारात्मक उपायों को रेखांकित कीजिए।

भारत में लगातार बढ़ते शहरीकरण व शहरों की बढ़ती आबादी के कारण संधारणीय नदी प्रबंधन एक प्रमुख आवश्यकता बन गया है।

संधारणीय नदी प्रबंधन
- नदियों में वर्षभर ई-फ्लो सुनिश्चित करना
- नदियों को प्रदूषण से बचाना
- नदी क्षेत्रों के अतिक्रमण को रोकना।

चुनौतियां

→ बढ़ती आबादी की आवश्यकता की पूर्ति संबंधी दबाव।

→ स्लम बस्तियां को बढ़ावा मिलने के कारण नदी क्षेत्र का अतिक्रमण।

→ उद्योगों द्वारा अनुपचारित जल को सीधे

नदियों में निस्तारित करना।

→ शहरों में बिना उपचारित घरेलू जल को नदियों में निस्तारित करना।

→ शहरी अपशिष्ट का नदियों में निस्तारण।

इस संबंध में हाल ही में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत रिवर सिटीज अलायंस की घोषणा की गई है। यह शहरी नदी जल के संधारणीय प्रबंधन में सहायक होगा।

अन्य उपाय

→ शहरों में आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार।

→ उद्योगों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक को अपनाने हेतु प्रोत्साहन।

→ घरेलू सीवरेज के नदी जल में मिलने से पूर्व बायोरेमेडिएशन।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन।

→ स्लम बस्तियों के अतिक्रमण को रोकने हेतु इनका अन्य क्षेत्रों में पुनर्वास करना।

इस प्रकार संधारणीय नदी प्रबंधन SDG 14, SGD-6 (स्वच्छ जल) की प्राप्ति में सहायक होगा।

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Haphazard growth and poor management make the Indian cities the locus of disasters, both large and small. Comment. Also, discuss the current gaps in policies in addressing these challenges. **(250 words) 15**

अव्यवस्थित विकास तथा निम्न स्तरीय प्रबंधन ने बड़े और छोटे दोनों प्रकार के भारतीय शहरों को आपदाओं का केंद्र बना दिया है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इन चुनौतियों का समाधान करने में नीतियों में विद्यमान वर्तमान अंतराल पर चर्चा कीजिए।

भारत में आजादी के बाद से ही विशेषकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से शहरीकरण को बढ़ावा मिला। यद्यपि यह शहरीकरण नियोजित न होकर ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासियों व विभिन्न कंपनियों के आगमन से प्रेरित था।

~~इस अव्यवस्थित विका~~

इस कारण शहरों में अनियंत्रित स्लम, अनियोजित औद्योगिकीकरण की स्थापना हुई।

अव्यवस्थित विकास एवं निम्न स्तरीय प्रबंधन के कारण आपदाएं

→ **फ्लैश फ्लड** - कई भारतीय शहर जैसे

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

डीप संकल्पना के कारण भारी बारिश से उत्पन्न फ्लैश फ्लड से प्रभावित हो। साथ ही प्लास्टिक व भवन अपशिष्ट के प्रभावी निपटान न होने के कारण बाढ़ की पुनरावृत्ति हो रही है।

→ **आग** – शहरों में आबादी क्षेत्रों में अवैध कारखाने आग से निरंतर प्रभावित होते हैं।

→ **रासायनिक दुर्घटनाएं** – शहरों में बस्तियों के किनारे बसी फैक्ट्रियां से दुर्घटना की संभावना। इसके साथ ही वास्तव में अनियोजित शहरीकरण ने आपदाओं की भयावहता को बढ़ाने का काम किया है।

इन चुनौतियों के समाधान में नीतियों में अंतराल

→ प्रतिक्रियात्मक प्रयास – आपदाओं के पूर्व प्रभाव को कम करने आपदा पूर्व प्रयास की जगह वर्तमान में आपदा आने के बाद

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रतिक्रियात्मक प्रयासों पर अधिक जोर।

→ अनुपालन - विभिन्न कानून जैसे राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के मानकों का सख्त अनुपालन न किया जाना।

→ स्थानीय समुदाय - वर्तमान में आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी न के बराबर है।

→ अनियंत्रित विकास - वर्तमान में अवसंरचना निर्माण के दौरान संभावित आपदाओं को ध्यान में नहीं लिया जाता।

उपाय

- स्थानीय समुदाय के सहयोग से आपदा प्रबंधन।
- निष्क्रिय व प्रतिक्रियात्मक प्रयासों की जगह अग्रसक्रिय उपाय अपनाना।
- नियोजित शहरीकरण का प्रयास करना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Discuss the extent of the problem of narco-terrorism in India. What measures have been taken by the government to counter and control this problem? (250 words) 15

भारत में नार्को-आतंकवाद की समस्या के प्रसार पर चर्चा कीजिए। इस समस्या से निपटने और नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नार्को आतंकवाद से तात्पर्य मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के माध्यम से वित्तपोषित होने वाले आतंकवाद से है।

भारत में नार्को आतंकवाद का प्रसार

→ पूर्वोत्तर भारत में गोल्डन ट्राइएंगल (म्यांमार, थाइलैंड, लाओस) से मादक द्रव्य की आपूर्ति।

→ पूर्वोत्तर में अलगाववादियों द्वारा मादक द्रव्यों के व्यापार के माध्यम से विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा।

→ जम्मू एवं कश्मीर में गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान) से मादक द्रव्यों की आपूर्ति।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान की ISI की मदद से मादक द्रव्य व हथियारों का व्यापार करना।

→ वर्तमान में बिटकॉइन आदि के प्रचलन से नार्को आतंकवाद में वित्तपोषण में आसानी

→ भारत के कई राज्यों व शहरों जैसे पंजाब, मणिपुर, मुंबई में मादक द्रव्यों की माँग बढ़ने के कारण नार्को आतंकवाद का प्रसार।

सरकार द्वारा प्रयास

→ NCB की मदद से मादक द्रव्यों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई।

→ धनशोधन निषेध अधिनियम, 2002 का निर्माण।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ धनशोधन रोकने प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक शक्तियाँ।

→ सीमा पर चौकसी बढ़ाकर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं।

→ म्यांमार से सहयोग द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी रोकने का प्रयास।

→ सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा मादक पदार्थों का सेवन रोकने कार्ययोजना।

सुझाव

→ सीमा पर तैनात सशस्त्र बलों को मादक पदार्थों की तस्करी रोकने ट्रेनिंग।

→ सीमावर्ती राष्ट्रों से सहयोग।

→ युवाओं में मादक पदार्थों के कुप्रभावों के संबंध में जागरूकता।

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. The dark web can be an ideal platform for several criminal and terrorist activities. Discuss with examples. Also, suggest measures to tackle the misuse of dark web. **(250 words) 15**

डार्क वेब कई आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक आदर्श मंच हो सकता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। साथ ही, डार्क वेब के दुरुपयोग से निपटने के उपायों का सुझाव दीजिए।

डार्क वेब इंटरनेट का वह भाग है जो सामान्य जनता की पहुँच से दूर रहता है, इसे एक्सेस करने के लिए विशेष ब्राउजर जैसे TOR ब्राउजर की जरूरत होती है।

डार्क वेब : आपराधिक व आतंकवादी गतिविधियों के लिए आदर्श मंच

→ डार्क वेब में किये गये लेन-देन व विभिन्न गतिविधियों को ट्रैक करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए कठिन।

→ डार्क वेब में अनामिकता के कारण अपराधियों की पहचान मुश्किल।

→ यहाँ विभिन्न आतंकवादी व अपराधी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुरक्षा एजेंसियों के डर के बिना, आसानी से हथियार व मादक द्रव्यों की तस्करी संबंधी कार्य कर सकते हैं।
जैसे अलकायदा द्वारा डार्क वेब का उपयोग हथियारों की खरीद में।

डार्क वेब के दुरुपयोग से निपटने उपाय

→ सुरक्षा एजेंसियों को डार्क वेब संबंधी ट्रेनिंग देना।

→ विभिन्न ISP (इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर) कंपनियों की मदद से डार्क वेब की गतिविधियों की जाँच का प्रयास करना।

→ व्हाइट हैट हैकर्स जैसे तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं की मदद लेना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. What is catalysis? Highlight the characteristics of catalysts. Also, elaborate why catalytic reactions are important for human beings. **(250 words) 15**

उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरकों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाइए कि मानव के लिए उत्प्रेरकी अभिक्रियाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं।

उत्प्रेरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें भाग लेने वाला पदार्थ (उत्प्रेरक) स्वयं प्रत्यक्षतः रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। अपितु रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है।

उत्प्रेरक की विशेषताएं

→ रासायनिक क्रिया के बाद भी इसका परिमाण परिवर्तित नहीं होता है।

मानव के लिए महत्व

→ रासायनिक उत्पादों जैसे अमोनिया के निर्माण में।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Electric mobility offers solutions to the problems associated with climate change, growing fuel prices, and urban transportation issues. Discuss in the context of India. **(250 words) 15**

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जलवायु परिवर्तन, ईंधन की बढ़ती कीमतों और शहरी परिवहन के मुद्दों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से तात्पर्य विद्युत संचालित यातायात / परिवहन प्रणाली से है जैसे ई-स्कूटी।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का महत्व –

1. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में :–

→ शून्य GHG उत्सर्जन के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण में।

→ इनमें से कोई भी हानिकारक प्रदूषक गैसें जैसे SO_2, NO_2 का उत्सर्जन नहीं होता है।

2. ईंधन की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में –

→ ई-व्हीकल्स विद्युत संचालित होने के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कारण इनका मूल्य पेट्रोल, डीजल संचालित वाहनों से कम होता है।

→ ये आयात पर आधारित ईंधन पर निर्भर न होने के कारण बाह्य आपूर्ति अवरोधों से सुरक्षित।

3. शहरी परिवहन के संदर्भ में:-

→ बिना शोर एवं वायु ~~प्रदूषण के~~ प्रदूषण के शहरी यातायात व्यवस्था का संचालन।

→ शहरों में परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण कों कमी से नागरिक के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव।

सरकार द्वारा प्रयास

→ फेम पहल के माध्यम से ई-व्हीकल्स को बढ़ावा।

→ COP-26 में ई-अमृत पोर्टल की घोषणा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का निर्माण।

सुझाव

→ स्वदेशी बैटरी निर्माण में शोध को प्रोत्साहन।

→ ई-व्हीकल्स को वहनीय बनाने हेतु सब्सिडी व कर प्रोत्साहन।

ई-मोबिलिटी को बढ़ाना भारत को प्रदूषण से लड़ने व सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा।